

इनसाइट: ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटन के लिये ज़रूरी है भारत

संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों के 25वें शिखर सम्मेलन में हसिसा लेने के लिये हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 से 20 अप्रैल तक ब्रिटन की यात्रा पर गए थे। इस सम्मेलन से इतर भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिटन की प्रधानमंत्री टेरीज़ा मे के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर वसितार से चर्चा की। यूरोपीय संघ से ब्रिटन के बाहर आने के साए तले हुई इस बैठक का महत्त्व कही अधिक था क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद की वैश्विक राजनीति में ब्रिटन को एक नई पहचान की ज़रूरत है।

यदि सबकुछ ठीक रहता है तो आधिकारिक रूप से निर्धारित दो साल की बातचीत के बाद मार्च 2019 तक ब्रेक्सिट की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिये। उल्लेखनीय है कि ब्रेक्सिट के बाद भारत के साथ नई आर्थिक साझेदारी वकिसति करने के उद्देश्य से ब्रिटन सरकार द्वारा पुख्ता नीव रखने के साथ ही भारत के साथ उसके संबंध 2017 में तब और मज़बूत हुए, जब इसे ब्रिटन-भारत सांस्कृतिक वर्ष के रूप में मनाया गया।

वभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति

- भारत और ब्रिटन ने आपसी सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिये तकनीकी, व्यापार और नविश के मुद्दों सहित नौ समझौतों पर हस्ताक्षर किये।
- दोनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सूचनाओं के आदान-प्रदान और सहयोग के लिये भी सहमतिपत्र पर हस्ताक्षर किये।
- अपराधियों के रिकार्ड के आदान-प्रदान के साथ ही संगठित अपराधों को खत्म करने के लिये भी दोनों देशों में सहमति बनी।
- दोनों देशों के बीच साइबर संबंधों के साथ ही स्वतंत्र, मुक्त, शांतपूरण और सुरक्षित साइबर स्पेस के संबंध में समझौते के अलावा, साइबर सुरक्षा प्रबंधन पर भी सहमति बनी।
- दोनों देशों की सेनाओं के बीच नकट संबंधों और महत्त्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों में रक्षा क्षमता भागीदारी जैसे कई समझौतों पर भी वचिार कया गया।
- ब्रिटन-भारत संयुक्त व्यापार समीक्षा के दौरान बाधाओं को दूर करने और दोनों देशों में कारोबार को सुगम बनाने तथा भविष्य के लिये मज़बूत द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध बनाने जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई गई।
- दोनों देशों ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नई भागीदारी पर भी वचिार-वमिर्श कया। इस भागीदारी से दोनों देशों में हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलने और नविश बढ़ने की उम्मीद है।
- भारत और ब्रिटन आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, कट्टरवाद और ऑनलाइन कट्टरवाद जैसे वभिन्न मुद्दों पर समान वचिार रखते हैं।

भारत यह मानता है कि ब्रिटन के यूरोपीय संघ से अलग होने से द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने के बेहतर अवसर मिले हैं। ब्रिटन ने भारत को यूरोपीय संघ से बाहर नकिलने की प्रक्रिया की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि इस बारे में मार्च में जो अवधितय हुई है उसमें भारतीय कंपनियों और नविशकों को आश्वस्त कया गया है कि उनके लिये बाज़ार में प्रवेश की मौजूदा शर्तें 2020 तक जारी रहेंगी।

ब्रिटन-भारत प्रौद्योगिकी भागीदारी

- ब्रिटन-भारत प्रौद्योगिकी भागीदारी दोनों देशों के बीच सहयोग का एक बड़ा आधार है। इसके तहत दोनों देश ज्ञान और अनुसंधान में सहयोग तथा अपने वशि्वस्तरीय नवाचार समूहों के बीच साझेदारी बनाने का काम करेंगे।
- वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिये दोनों पक्ष अपने युवाओं के कौशल और क्षमताओं को वकिसति करते हुए भविष्य की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे; आर्टफिशियल इंटेलीजेंस की क्षमता को साकार करेंगे; डिजिटल अर्थव्यवस्था; स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों; साइबर सुरक्षा और स्वच्छ विकास, स्मार्ट शहरीकरण तथा भविष्य की गतिशीलता को बढ़ावा देंगे।
- प्रौद्योगिकी साझेदारी के तहत ब्रिटन में ब्रिटन-भारत टेक हब स्थापित करने की पहल की गई है। यह टेक हब उच्च तकनीकी कंपनियों को एक साथ लाने के लिये नविश और नरियात के अवसर तैयार करेगा और भविष्य की गतिशीलता, उन्नत वनिर्माण तथा भारत के आकांक्षी ज़िलों के कार्यक्रमों के तहत हेल्थकेयर के क्षेत्र में बेहतरीन तकनीक और अग्रिमि नीति सहयोग को साझा करने के लिये एक नया मंच प्रदान करेगा।
- नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिये ब्रिटन और भारत के बीच क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर भागीदारी की जाएगी। दोनों देशों के सहयोग से भारत-ब्रिटन तकनीकी सीईओ गठबंधन बनाया जाएगा।
- वैश्विक चुनौती से निपटने के लिये दोनों पक्ष वजिज्ञान अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और ब्रिटन की बेहतरीन प्रतभाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रिटन अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है। वर्ष 2008 से शुरू हुए ब्रिटन-भारत न्यूटन-भाभा कार्यक्रम के तहत 2021 तक संयुक्त अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में 400 मिलियन पाउंड से ज्यादा राशिके पुरस्कार प्रदान किये जाने हैं।

व्यापार, नविश और वक्ति

- भारत और ब्रिटिन परस्पर व्यापार के लिये नई व्यवस्था विकसित करने हेतु साझा पूरक क्षमताओं के माध्यम से व्यापारिक साझेदारी को एक नया रूप दे रहे हैं।
- ब्रिटिन-भारत संयुक्त व्यापार समीक्षा बैठक के सुझावों के आधार पर व्यापार की बाधाओं को कम करने के लिये कषेत्रवार रोडमैप तैयार करने के साथ परस्पर व्यापार को सुगम बनाने और यूरोपीय संघ से ब्रिटिन के अलग हो जाने के बाद द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिये मलिकर काम करने पर सहमत बनी है।
- यूरोपीय संघ से ब्रिटिन के निकल जाने के बाद की अवधि में भारत यह सुनिश्चित करेगा कि ब्रिटिन-भारत समझौते को लागू करने के प्रयास आगे भी जारी रहें।
- दोनों देश नयिम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था पर विश्वास करते हैं तथा सतत टिकाऊ विकास और प्रगति के लिये मुक्त, नष्पिक्ष और खुले व्यापार के महत्त्व को स्वीकारते हैं।
- भारत ने ब्रिटिन में भारतीय नविश के लिये एक पारस्परिक फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित कर भारतीय व्यवसायों को अतिरिक्त समर्थन प्रदान किया है।
- इसके अलावा दोनों देशों के बीच प्रस्तावित नए नयिमक सहयोग समझौते सहित दोनों देशों के बीच फनिटेक वार्ता शुरु करने पर सहमत बनी है।
- वक्तिीय सेवाओं के सहयोग को तकनीकी मदद से बढ़ाया जाएगा, ताकि दिवालियापन, पेंशन और बीमा कषेत्र के बाज़ारों को विकसित किया जा सकें।

(टीम वृषटि इनपुट)

क्यों ज़रूरी है ब्रिटिन के लिये भारत?

- ब्रेक्सिट के फैसले के बाद भारत-ब्रिटिन संबंधों पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ना तय है। भारत ब्रिटिन का महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। इसीलिये ग्लोबल ब्रिटिन की बात कहते हुए प्रधानमंत्री बनने के बाद टैरीज़ा मे ने अपने पहले वदिश दौर के लिये भारत को चुना था।
- ब्रिटिन की कुल जीडीपी में प्रवासी भारतीयों का लगभग 6% योगदान है।
- इन सबके बावजूद भारत-ब्रिटिन का व्यापार काफी कम है, जसि बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिये भारत को बारीकी से ब्रेक्सिट की प्रक्रिया पर नज़र रखनी होगी।
- ब्रिटिन यूरोपीय संघ के कस्टम यूनियन में बना रहता है तो भारत को ब्रिटिन के बजाय यूरोपीय संघ से डील करनी पड़ेगी।
- ब्रिटिन कारों पर आयात कर कम करने के साथ ही वक्तिीय सेवाओं और कानूनी फर्मों के भारत में प्रवेश की मांग करता रहा है, लेकिन भारत को अपने हितों पर भी ध्यान देना होगा।
- यूरोपीय संघ से बाहर होने के बाद ब्रिटिन का इससे व्यापार कम हो जाएगा और इसकी कषतपूर्ति हेतु ब्रिटिन भारत से व्यापार बढ़ाने को उत्सुक है।
- भारत को ब्रिटिन के साथ अप्रवासन संबंधी मुद्दों को हल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रिटिन भारत को इस मामले में कोई रथियात देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन भारत यह स्पष्ट कर चुका है कि यह रवेया दोनों देशों के हित में नहीं है।
- भारत और यूरोपीय संघ के बीच सबसे बड़ा गतिरिध कृषि कषेत्र की सब्सिडी को लेकर है, परंतु भारत-ब्रिटिन के बीच ऐसी कोई बाधा कृषि सब्सिडी को लेकर नहीं है।

इन कषेत्रों में ब्रिटिन कर सकता है भारत के साथ सहयोग

- भारत में विकास के लिये वदिशी नविश की आवश्यकता है और ब्रिटिन पूंजी नविश जुटाने और उसे क्रयान्वति करने की दक्षता रखता है।
- भारत सड़कों, मेट्रो, रेलमार्गों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों के रूप में आधारभूत संरचना का विकास कर रहा है और ब्रिटिन को आधारभूत संरचना नरिमाण के कषेत्र में विशेषज्ञता हासलि है।
- भारत को नए शहर बसाने तथा अपने मौजूदा शहरों के वसितार की ज़रूरत है और ब्रिटिन को शहरी नयिोजन एवं स्थापत्य नरिमाण में महारत हासलि है।
- भारत मूल्य शृंखला के ऊपरी सरि पर एक वृहत्तर वनिरिमाण कषेत्र का नरिमाण करना चाहता है तथा ब्रिटिन वशिज्ञतापूर्ण उच्च प्रोद्योगिकी युक्त ऐसे आवश्यक वनिरिमाण में दक्ष है।
- भारत को कोयला, तेल और गैस जैसे परंपरागत तथा पवन एवं सौर जैसे नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन की आवश्यकता है और ब्रिटिन इन सभी कषेत्रों में विशेषज्ञता रखता है।
- भारत को ज़रूरत है अगले दस वर्षों में श्रम बाज़ार में शामिल होने वाले 50 करोड़ युवाओं को शक्ति-प्रशक्ति करने की और ब्रिटिन शक्ति एवं कौशल-विकास का हुनर रखता है।
- भारत को अपने 1.2 अरब लोगों के लिये बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा की ज़रूरत है और स्वास्थ्य सेवा एवं औषधिक कषेत्र में ब्रिटिन के पास व्यापक दक्षता है।
- अब, जबकि भारतीय कंपनयिों ने वैश्विक स्वरूप हासलि कर लिया है तो उन्हें ब्रिटिन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली बैंकिंग, बीमा, अकाउंटेंसी, कानून आदि जैसी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है।
- भारत वैश्विक बाज़ार में अपनी पहूँच चाहता है। ब्रिटिन एक व्यापक आधार स्थल है जहाँ से दुनिया के सबसे बड़े एकल बाज़ार--यूरोपीय संघ तक पहुँचा जा सकता है।

ब्रिटिन पछिले दस वर्षों में भारत में जी-20 का सबसे बड़ा नविशक देश रहा है, जबकि भारत ब्रिटिन में नविश परयिोजनाएं लगाने के मामले में चौथा सबसे बड़ा देश रहा है। भारत के लिये ब्रिटिन एक महत्त्वपूर्ण आयातक देश है, हालाँकि यह भारत को बड़ी मात्रा में नरियात भी करता रहा है, लेकिन हाल के समय में इसमें कमी आई है। ब्रिटिन की अर्थव्यवस्था में भारत की कंपनयिों की अहम भूमिका है, 800 से ज़्यादा ऐसी कंपनयिों ने ब्रिटिन में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया है।

दोनों देशों के आपसी संबंधों को मज़बूत बनाए रखने में ब्रिटन में रहने वाले करीब 15 लाख प्रवासी भारतीयों की अहम भूमिका है। ये प्रवासी भारतीय न केवल ब्रिटन और भारत के बीच एक पुल का काम कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने भारत की संस्कृति से ब्रिटन को संपन्न भी किया है। प्रवासी भारतीय ब्रिटन में हर क्षेत्र में मौजूद हैं, चाहे व्यापार, राजनीति, खेल का क्षेत्र हो या कोई और, इन्होंने सबमें एक मुकाम हासिल किया है। यह भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं कि ब्रिटन ने आपसी संबंधों को बेहतर करने लिये ज्यादातर प्रवासी भारतीयों को ही माध्यम बनाया है।

क्या है ब्रेक्सिट (Brexit)?

- यूरोपीय संघ में रहने या न रहने के सवाल पर ब्रिटन में 23 जून 2016 को जनमत संग्रह कराया गया था, जिसमें लगभग 52% मतदाताओं ने यूरोपीय संघ से बाहर होने के पक्ष में मतदान किया था।
- इसे ब्रेक्सिट कहा गया अर्थात् ब्रिटन+एग्जिट को मिलाकर ब्रेक्सिट शब्द की उत्पत्ति हुई।
- जनमत संग्रह में केवल एक प्रश्न पूछा गया था--क्या यूनाइटेड किंगडम को यूरोपीय संघ का सदस्य बना रहना चाहिये या इसे छोड़ देना चाहिये?
- ब्रेक्सिट तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन का चुनावी वादा था, इसीलिये यह जनमत संग्रह हुआ। हालांकि, वह खुद ब्रिटन के यूरोपीय संघ में बने रहने के पक्षधर थे।
- यहाँ यह बता देना समीचीन होगा कि 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के कार्यकाल में ब्रिटन यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था, लेकिन ब्रिटन ने साझा मुद्रा यूरो नहीं अपनाई... शेंगेन (Schengen) के पासपोर्ट-मुक्त क्षेत्र से बाहर रहा...अपनी मुक्त बाज़ार नीति जारी रखी।
- ब्रिटन वासियों ने 1975 में हुए एक जनमत संग्रह में यूरोपीय संघ में बने रहने के पक्ष में मतदान किया था, उस समय इसका नाम यूरोपीय इकनोमिक कम्युनिटी था। ब्रिटन 1 जनवरी, 1973 को इसका सदस्य बना था। इस समूह की शुरुआत 1957 में छह यूरोपीय देशों के बीच हुई रोम संधि से हुई थी। यूरोपीय संघ का वर्तमान स्वरूप 1993 में सामने आया था।

(टीम दृष्टि इनपुट)

निष्कर्ष: दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में साझा मूल्यों, समान कानूनों और संस्थानों के आधार पर, अपनी रणनीतिक भागीदारी को मज़बूत करने की ब्रिटन और भारत की स्वाभाविक महत्त्वाकांक्षा है। दोनों देश वैश्विक दृष्टिकोण और एक नयिम-आधारित ऐसी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के प्रति विचनबद्धता का हिससा हैं जो उन एकतरफा उठाए गए कदमों का जोरदार विरोध करती हैं जो बल के माध्यम से इस प्रणाली को कमज़ोर करना चाहते हैं। दोनों देश अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिये प्रतिबद्ध हैं, जिसका विस्तार समूचे विश्व में हो। दोनों देश अपने व्यावसायिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंधों को उन अनेकानेक गतिविधियों का पूरा लाभ उठाने के लिये प्रोत्साहित करते हैं जो भारत और ब्रिटन को पारिवारिक स्तर से लेकर वित्तीय व्यवस्था तथा व्यवसाय से लेकर बॉलीवुड तक और खेल से लेकर विज्ञान तक परस्पर जोड़ते हैं। संपन्न लोकतंत्र के रूप में भारत और ब्रिटन उन सभी के साथ मिलकर काम करने की इच्छा साझा करते हैं जो नयिम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों, वैश्विक शांति और स्थिरता के पक्षधर हैं।